

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1327 व 1328/2011/सीकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीकर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अनुपम फर्नीचर हाऊस, सीकर।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव कासलीवाल,

राजकीय उप अभिभाषक।

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.07.2014

निर्णय

उक्त दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सीकर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जावेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स-तृतीय), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जावेगा) के अपील संख्या 170 व 171/अपील्स-चतुर्थ/2009-10/सीकर में पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 09.12.2010 के विरुद्ध पेश की गयी हैं जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2006-07 व 2007-08 के लिये पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 31.08.2009 में क्रेडिटनोट्स से प्राप्त राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, रिवर्स कर ₹4,76,743/- व ₹3,89,073/- की कायम मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

अपील संख्या 3127/2011/सीकर के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2006-07 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 के तहत दिनांक 28.01.2009 को पारित किया गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने पारित निर्धारण आदेश व रिकॉर्ड पत्रावली के पुनः अवलोकन पर यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में 4 प्रतिशत की दर से ₹2,35,78,239/- के क्य किये गये मोबाईल हैण्डसेट ₹1,19,18,566/- पर 4 प्रतिशत की दर से चुकाये गये कर के संबंध में ₹4,76,743/- का आगत कर का मुजरा चाहा/प्रतिदाय चाहा गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(36) में दी गयी विक्रय कीमत की परिभाषा के द्वितीय

लगातार.....2

अपील संख्या-1327 व 1328 / 2011 / सीकर

परन्तुक के अनुसार विक्रय के समय बीजक से यथा प्रकट नकद या व्यापार डिस्काउण्ट विक्रय कीमत में से अपवर्जित करने व भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये कोई भी डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन या रिबेट या पुरस्कार आदि अपवर्जित नहीं किये जाने के आलोक में, व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त डिस्काउण्ट/सबसीडी के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के अभाव में सुनवायी उपरांत व प्रत्यर्थी व्यवहारी को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् मूल निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2009 के जरिये अतिशेष रहे आधिक्य ₹5,75,656/- में से ₹4,76,743/- कम कर, शेष ₹98,913/- का समायोजन प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्धारण वर्ष 2007-08 के कर के पेटे दिये जाने संबंधी आदेश अधिनियम की धारा 33 के तहत दिनांक 31.08.2009 को पारित किये गये। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील संख्या 3128 / 2011 / सीकर के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2007-08 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24(4) के तहत दिनांक 31.08.2009 को पारित करते समय, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में 4 प्रतिशत की दर से ₹2,16,74,426/- के क्रय किये गये मोबाईल हैण्डसेट ₹8,66,977/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया है। उक्त क्रय पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ₹97,26,849/- की सबसीडी क्लेम करने हुये उक्त पर 4 प्रतिशत की दर से चुकाये गये कर ₹3,89,073/- का आगत कर का मुजरा चाहा/प्रतिदाय चाहा गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धरा 2(36) में दी गयी विक्रय कीमत की परिभाषा के द्वितीय परन्तुक के अनुसार विक्रय के समय बीजक से यथा प्रकट नकद या व्यापार डिस्काउण्ट विक्रय कीमत में से अपवर्जित करने व भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये कोई भी डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन या रिबेट या पुरस्कार आदि अपवर्जित नहीं किये जाने के आलोक में, व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त डिस्काउण्ट/सबसीडी के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के अभाव में सुनवायी उपरांत व प्रत्यर्थी व्यवहारी को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् निर्धारण आदेश दिनांक 31.08.2009 को पारित कर चाहे गये आगत कर के मुजरे/प्रतिदाय ₹3,89,073/- को अस्वीकार कर दिया।। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण

अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये प्रतिदाय/आगत कर का मुजरा राशि के संबंध में दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त को अस्वीकार किया गया है। कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को समुचित अवसर प्रदान किया गया था परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी चाहे गये दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुये जिसके उपरांत अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के संबंध में निर्धारण आदेश पारित कर, रिवर्स कर की मांग राशियां कायम की गयी हैं जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी का कथन है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2006-07 के संबंध में मूल निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 33 के तहत निर्धारण आदेश पारित कर, मांग राशि कायम की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2006-07 व 2007-08 का मूल निर्धारण आदेश प्रस्तुत दस्तावेजों में घोषित संव्यवहारों को स्वीकार कर, पारित किया गया था तत्पश्चात् महालेखाकार/ऑडिट आक्षेप के आधार पर राय परिवर्तन कर, मांग वसूली हेतु मांग राशि कायम कर, स्वीकृत आगत कर की मुजरा राशि पर रिवर्स कर आरोपित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स ड्राईव इण्डिया काम. लि., जयपुर का एक अधिकृत डीलर है जिसके द्वारा मोबाईल्स क्रय किये गये हैं एवम् उक्त संव्यवहार प्रत्यर्थी व्यवहारी के बहीयात में दर्ज है। कथन किया कि मोबाईल्स की खरीद बढ़ाने के उद्देश्य से मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि., द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को 1,19,18,566/- की सब्सीडी प्रदान की गयी जो कि विक्रेता व्यवहारी से एक पृथक फर्म है। कथन किया कि टाटा टेली सर्विसेज द्वारा प्रदान की गयी उक्त सब्सीडी को मैसर्स ड्राईव इण्डिया काम., लि., जयपुर अब मैसर्स ड्राईव इण्डिया एन्टरप्राइजेज सोल्यूशन लि., की सब्सीडी नहीं माना जा सकता। अपने उक्त तर्क के समर्थन में 124 एस.टी.सी. 586 (सु.को.) मैसर्स नैवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, मैसर्स टिस्को जनरल ऑफिस, रिक्रेशन क्लब बनाम् बिहार राज्य व अन्य (2002) 126 एस.टी.

सी. 547 को प्रोद्धरित किया गया ।

कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सब्सीडी प्रदानकर्ता मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज है एवम् इसी कारण सब्सीडी मैसर्स ड्राईव इण्डिया काम.लि. ( अब मैसर्स ड्राईव इण्डिया एन्टरप्राइजेज सोल्यूशन लि. ) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रय किये गये माल से संबंधित नहीं है । अतः पारित निर्धारण आदेश में सब्सीडी पर अस्वीकार कर, कायम रिवर्स कर की मांग राशियां अविधिक है । कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मोबाईल क्य के पेटे प्राप्त हुयी सब्सीडी राशियों पर आगत कर का मुजरा अस्वीकार कर, अतिशेष कर, अधिक्य से कम किया गया है जो अविधिक है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने क्य राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया है परन्तु उक्त माल का विक्रय पहले मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज से मोबाईल हैण्ड सेट की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी व्यवहारी को सब्सीडी प्रदान की गयी । इसी कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल प्राप्त सब्सीडी को ध्यान में रखते हुये क्य मूल्य से कम दर पर विक्रय किया परन्तु अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध रिवर्स कर की मांग राशियां कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं जो अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया गया है ।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वेट अधिनियम की धारा 2(33) में परिभाषित रिवर्स टैक्स के अनुसार वेट अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज 'ए' से 'जी' तक की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर ही पूर्व में क्रेडिट किया गया इनपुट टैक्स रिवर्स हो सकता है। प्रत्यर्थी ने धारा 18 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

विद्वान अभिभाषक का अग्रिम कथन है कि वेट अधिनियम की धारा 18(3ए) का संशोधन दिनांक 09.03.2011 भूतलक्षी न होकर दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में क्रय किये गये किसी माल की पश्चातवर्ती आर्थिक सहायता (subsidy) के आधार पर कम कीमत पर बिक्री होने पर ऐसे माल पर अनुज्ञेय इनपुट टैक्स विक्रय मूल्य पर देय आउटपुट टैक्स से अधिक नहीं होगा। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18(3ए) के दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी प्रावधानों के अनुसरण में पूर्ववर्ती अवधि में ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, वैट आरोपण का आदेश अविधिक एवं अनुचित होने से इस आदेश को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स

अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी उदयपुर; अपील संख्या 650 से 654/2012/जालौर, अपील संख्या 853 से 861/2012/जालौर निर्णय दिनांक 19.12.2012, माननीय केरला उच्च न्यायालय के प्रिया एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 14 वी.एस.टी. 293 एवं माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के मद्रास सीमेंट लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 35 वी.एस.टी. 14, 124 एस.टी.सी. 586 (सु.को.) मैसर्स नैवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद, वैट-07 में दर्शायी गयी खरीद से कम दर्शायी गयी है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुये वैट आरोपित किया गया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रेता द्वारा जारी ट्रेड डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी का विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। विक्रय मूल्य की परिभाषा वैट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार निम्न प्रकार है:-

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

**Explanation I.** - In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

**Explanation II.** - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

अपील संख्या-1327 व 1328 / 2011 / सीकर

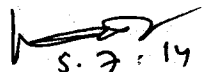
**Explanation III.** – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स नैवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (124 एस.टी.सी. 586) के प्रकरण में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:-

“It is that sale consideration, whether in cash or otherwise, which is receiveable in respect of sales made by the dealer which can possibly form part of the turnover of a dealer. It is that sum which can be legitimately regarded as forming part of the aggregate amount for which the goods have been bought or sold. The sum has to be paid either by purchaser or on his behalf by some other person. Any sum received *de hors* the contract of sale from another entity, whether it be the Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is payable.” इस प्रकार प्रत्यर्थी के विक्रेता द्वारा क्रेडिट नोट से प्राप्त राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आरोपित आरोपित वैट को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

परिणामस्वरूप, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
5. 7. 14  
( मदन लाल )  
सदस्य